

उपसभापति : फिर शिकायत मत कीजिए ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : ग्रहलुवालिया जी से लेकर यहां तक अगर सब मान लेते हैं कि कोई इन्टरप्ट नहीं करेगा ... (व्यवधान)

उपसभापति : अगर इन्टरप्ट करेंगे तो उलटा जवाब मिलेगा । इसलिए उनको बोलने दोजिए । मैं सबसे यह रिक्वेस्ट करूंगी कि जो अपना भाषण कर रहा है उसको वह भाषण करने दें । जिस पार्टी का समय आये वह अपना उस समय जवाब दे । जब इन्टरप्ट होती है तो उसका नुकसान होता है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अगर यह शराफत और ईमानदारी सब में होती है तो मुझे मंजूर है लेकिन है नहीं । (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kulkarni, will you continue after lunch or do you want to finish?

SHRI A. G. KULKARNI: I will finish within five minutes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: For five minutes more you speak and I will then adjourn. (*Interruptions*).

SHRI A. G. KULKARNI: Madam, I will speak after lunch.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 2.30 for lunch.

The House then adjourned for lunch at thirty-four minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-two minutes past-two of the clock. **THE VICE CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN)** in the Chair.

Calling Attention to a matter of urgent Public importance Communal situation in the country—Contd.

SHRI V. NARAYANASAMY: (Pondicherry): Happy New Year, Madam. You

are setting in the Chair for the first time now.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Now, Shri Satya Prakash Malaviya to make a statement regarding enhancement of LPG priority quota.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Before he starts, I want to know whether it is a practice to distribute it before the Minister starts because this is given to us. I hope we can claim in future in advance. I just want a clarification on this.

पेंडोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्यप्रकाश मालवीय) : अभी तो मैं पढ़ना शुरू करूंगा ।

श्री सन्तोष बागडोडिया: मंत्री महोदय के आने के पहले ही यह हमारे हाथ में आ गया है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I will find how it happened.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: If that is the practice. I don't mind. That suits us.

AN HON. MEMBER: That is not the practice.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): We will find out how it happened.

STATEMENT BY MINISTER

Enhancement of LPG Priority quota to be released on recommendations of Members of Parliament

पेंडोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्यप्रकाश मालवीय) : महोदया, मैं इस सम्माननीय संसद के माननीय सदस्यों को, संसद सदस्यों की अनुमति पर दिए जाने वाले एल पी. जी. के प्राथमिकता-कोटे में वृद्धि करने के संबंध में लिए गए निर्णय से अवगत कराना चाहता हूँ ।

वर्तमान खाड़ी संकट तथा एल०पी० जी० की सीमित उपलब्धता की वजह से चालू वर्ष में नए एल पी जी० उपभोक्ताओं का नामांकन करना संभव नहीं पाया गया है जैसा कि पहले किया जाता था। इसके परिणामस्वरूप, प्रतीक्षा-सूची में संभावित उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो गई है। लोगों की भारी मांग को पूरा करने के लिए संसद-सदस्य अपनी अनुशंसाओं पर दिए जाने वाले प्राथमिकता वाले एल.पी.जी. कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि करने के लिए अनुरोध करते रहे हैं। समुचित विचार के बाद, संसद-सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संसद सदस्य की अनुशंसा पर दिए जाने वाले एल०पी०जी० कनेक्शनों के कोट में एक कलेन्डर वर्ष में अपने वर्तमान 24 कनेक्शनों में वृद्धि करके पहली जनवरी, 1991 से 48 कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया है।

श्री अन्तोष बागड़ोदिया (राजस्थान) : महोदया, मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 24 कनेक्शनों से 48 कनेक्शन्स कर दिये हैं। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि 24 से 48 कनेक्शन्स हो गये हैं। अब संसद सदस्य खूलकर बांट सकते हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि एलोकेशन के लिए जब नाम दिये जाते हैं तो आप कितने दिनों में एलोकेशन कर देते हैं? कई केसों में तो ऐसा होता है कि साल भर में भी एलोकेशन नहीं होती है। और अगर आपने चिट्ठी दे दी और एलोकेशन हो गया तो उसकी सप्लाय नहीं है। ऐसे हमारे पास बहुत से केसेज हैं। जहाँ तक शहरों का सवाल है वहाँ फिर भी मिला जाता है लेकिन जो गांव के लोगों को देते हैं तो वे दंडते फिरते हैं कि कहां से वे सिलेंडर लायें। उनके पास चिट्ठी नहीं पहुंचती और अगर चिट्ठी पहुंच गई तो वे यह नहीं जानते कि कहां से गैस लें। इसका आप कोई रास्ता निकालें। साथ ही यह भी आप तय करें कि जिसको आप अलॉट करें उसके लिये कोई टाइम लिमिट निश्चित करें कि इतने दिनों तक उसको गैस निश्चित रूप से मिल जायेगी। (व्यवधान)

महोदया, यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह क्वेश्चन इतना लंबा-चौड़ा नहीं है लेकिन महोदया, क्या होता है कि एक ग्राहक सिलेंडर अलॉट कर देते हैं लेकिन उनको। उसका कोई रिप्लेसमेंट मिलता नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा करप्शन है। व जब लेने जाते हैं तो बोलते हैं कि अभी है नहीं। वहां लाइन लगी रहती है और ब्लैक-मार्केटिंग होती है। इसका भी आप कोई इंतजाम करें जिससे ब्लैकमार्केटिंग न हो... (व्यवधान) अब मिश्रा जी कह रहे हैं बस। लेकिन जब ये बोलते हैं तो इनको कोई नहीं रोक सकता लेकिन क्योंकि मैं मिश्रा जी की इज्जत करता हूँ कि इस लिये बस करता हूँ।

श्री मोहम्मद खलोलुर रहमान (ग्राध्र प्रदेश) : मैडम, अभी माननीय मंत्री जी ने जो एल पी जी. कोटा 24 से 48 का किया है, उसके ताल्लुक से मैं यह बोलना चाहता हूँ कि हम यह देख रहे हैं कि हम जब रेकमंड करते हैं तो तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच महीने हो जाते हैं मगर वे कनेक्शन नहीं मिल पाते हैं। जरूरत इस बात की है कि रेकमंड करने और जब एम०पी० रेकमंड कर देता है तो वे कनेक्शन जल्दी से जल्दी मिलेंगे। लेकिन जब 24 में ही कनेक्शन नहीं मिलता था तो मुझे इस बात का पूरा शुबहा है कि फिर 48 में कनेक्शन कैसे मिलेंगे? मैं उम्मीद करता हूँ कि मिनिस्टर साहब इस तरफ अपनी तवक्को करेंगे।

दूसरा मैं यह कहना चाहता हूँ कि एम०पी०जी० के घरों में जो गैस है तो जब सिलेंडर खत्म हो जाते हैं तो हम टेलीफोन करते हैं। लेकिन सिलेंडर आने में आठ-आठ दिन लग जाते हैं टेलीफोन पर यह बताने के बावजूद कि यह एम०पी० का कनेक्शन है और उनको घर में सिलेंडर चाहिए। मगर आठ-आठ दिनों तक सिलेंडर नहीं आते हैं। मैं मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि वे इस तरफ अपनी तवज्जह फरमायें ताकि एम०पी०जी० को जल्दी सिलेंडर मिलें।

† [شری محمد خلیل الرحمان
 (آندھرا پردیش): مہتمم کو مانگتے
 ملتوی کر کے جو اپیلیں جی کوٹا
 ۲۴ سے ۲۸ کا لپٹا ہے۔ اس کے تعلق
 سے میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہم
 یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب
 ریکمڈ کرتے ہیں تو تین تین چار
 چار مہینے ہو جاتے ہیں مگر وہ
 کنڈیکشن نہیں مل پاتے ہیں۔ ضرورت
 اس بات کی ہے کہ ریکمڈ کرنے اور
 جب ایم پی ریکمڈ کر دیتا ہے تو
 کنڈیکشن جلدی سے جلدی ملوں۔
 لیکن جب ۲۴ میں ہی کنڈیکشن
 نہیں ملتا تھا تو مجھے اس بات کا
 پورا شدید ہے کہ پھر ۲۸ میں کنڈیکشن
 کیسے ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں
 کہ منسٹر صاحب اس طرف اپنی
 توجہ کریں گے۔

دو-را میں یہ کہنا چاہتا ہوں
 کہ ایم پی کے گھروں میں جو گیس ہے
 تو جب سلنڈر ختم ہو جاتے ہیں تو
 ہم ٹیلیفون کرتے ہیں لیکن سلنڈر
 آنے میں آٹھ آٹھ دن لگ جاتے ہیں
 ٹیلیفون پر یہ بتانے کے باوجود کہ یہ
 ایم پی کا کمیشن ہے اور ان کو کس
 میں ملنڈر چاہئے۔ مگر آٹھ آٹھ
 دنوں تک سلنڈر نہیں آتے ہیں۔
 میں منسٹر صاحب سے درخواست
 کروں گا کہ وہ اس طرف اپنی توجہ
 فرمائیں تاکہ ایم پی کو جلدی سے
 جلدی سلنڈر ملے۔

SHRI KAPIL VERMA (Uttar Pra-
 desh): I join my colleagues in thanking
 the hon. Minister for increasing the LPG
 connection quota for us, particularly
 because the earlier Government, I am
 told, had decided only at 36 from 24,
 and this new Government has increased
 it to 48, though the figure of 36 was

† [] Transliteration in Arabic script.

not announced. Secondly, as some of
 my colleagues have said, after we make
 recommendation, quite a lot of time is
 taken in actually sanctioning it and still
 more time is taken in the intimation
 reaching the proper place and then the
 dealers to whom the intimation goes
 harass the people even when the origi-
 nal letter is shown to them as received
 by the MPs, and my personal experience
 is that the people who receive such
 quota have to face a lot of difficulty.
 In my hometown of Jaunpur district
 particularly, there is only one dealer
 and that place is crowded. The second
 dealer is not allocated these connections.
 In fact, there is a lot of corruption. I
 am taking advantage of the second para-
 graph, and the opening sentence about
 shortage, and therefore I feel what I
 am saying is relevant. There is a short-
 age of LPG, particularly now because
 of the Gulf crisis, and black-marketing
 is going on. Ordinary consumers—I am
 not speaking of MPs — are facing great
 hardship. In the city of Lucknow —
 and the hon. Minister knows quite well
 — I know from my personal experience,
 the gas agencies are indulging in large-
 scale corruption. In fact, these are
 sold away by dealers. The persons who
 take it actually sell it away on the way.
 A new system, 'cash and carry' from
 godowns has been introduced, instead of
 home delivery. This position has to
 be corrected immediately.

Since the hon. Minister has mentioned
 in the second paragraph of his state-
 ment about the shortage, I would like
 to know from him, what is the exact
 shortage and what is the position after
 the Gulf crisis? What is the waiting
 list of connections? I am told that it
 is about 25 to 30 per cent. What is
 the exact figure? What is the exact
 figure of the waiting list?

Another thing is, I am told that the
 ports which stock the imported LPG
 cannot handle more capacity and there
 is a proposal to arrange imports through
 other ports like Kandla, Mangalore and
 Ennore. What is the difficulty in
 arranging imports through other ports?
 How much foreign exchange will be
 required for this?

Apart from our making recommendations, the real point is the problem being faced by the common man. You are covering only 20,000. The waiting list is highly unrealistic because you are covering only a population of 20,000 and more. The limited number you are giving is highly insufficient. I am talking about the general public. Since you have mentioned about the shortage, I would like to know how soon will you be able to meet the shortage?

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Madam Vice-Chairman, the hon. Minister has said in his statement that because of the Gulf crisis, new enrolments are not being made in the current year. By increasing the quota for Members of Parliament from 24 to 48, we will have 36,000 connections. Not more than that. Now, when we talk about environmental protection, we find that the concentration is not on the rural side. Only the urban areas are being served.

When we approach the distributors, they say that their jurisdiction is only up to the town limits. I would like to cite an instance. A person from a village in my constituency approached me. I recommended his case. He was sanctioned one LPG connection. But when the person went to the distributor, he said, 'This is not within my jurisdiction'.

Therefore, the Minister has to review the system in regard to the supply being made by the distributors. There is also another aspect here. All the consumers are not taking delivery. But not even a single distributor is giving the estimate in regard to such cases. This aspect has also to be considered because corruption starts only from there. Not only that. The big businessmen, especially, those in the hotel industry, get cylinders by hook or crook, by paying extra money. As a result of this, the persons who have really to get the benefit are suffering. Then, I have another example of an industry which is an export-oriented,

hundred per cent export-oriented, industry. When Mr. Gurupadaswamy was the Minister of Petroleum, I wrote a letter to him that this industry should be given preference. Unfortunately, for eight months, the supply of cylinders could not be made to the industry which was earning more than Rs. 5 crores by way of foreign exchange. I suggest that such types of industries should be treated separately and they should be given preference. They should not be put on par with the local industries. Foundries also require LPG.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please conclude.

SHRI V. NARAYANASAMY: I am concluding. Another thing I would like to suggest here is, in the case of Members of Parliament who have been given this facility, the Petroleum Ministry should honour the MP's recommendations only in the case of the people of the constituency of the Member concerned.

I am suggesting, you can oppose it. It is my point of view. I am saying so because it is being considered as a racket. Madam, some persons come and request the Members to sign. He signs and those connections are sold in black market. Who is to blame for this? It is the Member of Parliament who is blamed for this. In order to avoid the blame on the Member of Parliament, I would request that the MP should recommend the cases of his constituency people only and only those recommendations should be accepted by the Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I would request the hon. Members not to take more than two minutes because we have to take up the discussion on the Calling Attention also. Yes, Shri A. G. Kulkarni.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR (Bihar): That was an advice and not a clarification.

SHRI V. NARAYANASAMY: Let him respond.

कृपया श्री व. नारायणसामी (महाराष्ट्र) :
कृपया साहब आपके बोलने के पहले

[कुनारी सरोज खाण्डे]

मैं सदन की ओर से यह कहना चाहती हूँ कि प्रधान मंत्री जी 1991 में आज पहली बार सदन में आये हैं अतः हम सबकी ओर से आपको बहुत बहुत शुभ-कामनायें। मैं आपके और प्रधान मंत्री जी के बीच खड़ी नहीं रहना चाहती हूँ।

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): For Heaven's sake, please do not bring me and let Prime Minister together because....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Pleased continue.

SHRI A. G. KULKARNI: I would only like to seek one or two clarifications. I am not interested in anything else, but Madam, I also extend to my friend and present Prime Minister many happy returns.

SHRIMATI MARGARET ALVA (Karnataka): Happy returns of what?

SHRI A. G. KULKARNI: Happy returns of the New Year. Do you follow?

Coming to the clarifications, I can also congratulate the Minister along with other friends, but I am sorry, this will give a wrong message to the people in the country that the quota for the Members of Parliament is increased while the general public is made to pay heavy price for getting one cylinder. Mr. Minister you must have recommended the cases earlier and you must be knowing it that now it has become a business and industry for many youth to carry cylinders and sell them in the villages at a very exorbitant price. Particularly, I know a case of Sangli where one agency was sought to be charge-sheeted but because of political influence the case was withdrawn. Mr. Minister, along with LPG connections there are many other problems. This will create a wrong impression of the Government. Your Government is only 2 months' old. Previous Government has suffered from this lacuna.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Is it your astrological prediction?

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : प्राइम मिनिस्टर साहब की समझ में आ गया है।

आपकी समझ में आया कि नहीं यह मुझे नहीं मालूम।

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्रशेखर) : मेरी समझ में आ गया है अब आप बैठ जाइये।

SHRI A. G. KULKARNI: So, Mr. Minister, you have to remove this impression and devolve a method whereby people will get LPG connections freely. You can increase its price by another Rs. 20, but do not make the people pay in black market.

Secondly, Mr. Minister, the diesel position is also very precarious. There are queues of trucks on the roads. What are you going to do about that? We have received a lot of complaints about diesel shortage and the truck transport has been severely hit by this shortage. The work in industries has come to a halt.

Industry can't deliver the goods and taxes are not collected. This is the problem. You please take this into consideration.

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Madam, I totally agree with Mr. Kulkarni. This announcement has made MPs happy, but I am not so happy because, Madam, there is a long pending list of new customers, and even old customers are not getting timely supplies of LPG cylinders. Now this decision of the Government will give a message to the people that now the only way of getting an LPG connection is to get hold of an MP, and all the MP's houses will be crowded by people who want LPG connections. Now, this is not going to solve the problem because the total number of LPG cylinders is the same, whether you increase the quota or not. This is not going to give any relief to the people, and only some people will get overriding priority on the basis of the recommendation of the MPs. Only this much is the difference. So, I would like to know from the honourable Minister what steps the Government is taking to ensure supply of cylinders at least to those who have registered their names

and what the Government is doing to quicken allotment to those who have already applied for registration. This is what the Government should do. I would request the Government that the quota, which was 24, let it remain. This will not help any MP. On the other hand, it will only embarrass the people, embarrass the MPs, and it is not going to help people except some lucky ones who have access to the MPs.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-MATI JAYANTHI NATARAJAN): Dr. Abrar Ahmed... Not here. Shri Hanumanthappa,

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Madam, I do not know whether the Minister is aware of the fact that the backlog of refill supplies, on an average, is three months. In some places it is two months. So, for two to three months individuals are not getting LPG cylinders. In such a situation, Madam, you can imagine the difficulties of a middle-class family which has disbanded the conventional modes of cooking. Now fuel is not available—kerosene is not available, there is power cut—and they have made arrangements for LPG, and LPG backlog is from three weeks to three months. Every company accepts that the backlog is between 21 and 90 days. Therefore, firstly the Minister should ensure, when once people become customers, that there is regular supply of gas. Otherwise, चूल्हा बन्द हो जाता है और खाना मुश्किल हो जाता है। इसके बारे में कुछ करना है। (व्यवधान)

Secondly, I support Mr. Narayanasamy. Madam, over the last eight years I am in Parliament and all my allotments have been signed at the various tables of this Secretariat—let me be very frank—because every table will be ready with a letter typed on the paper and they come for it. I have not been able to give, and if at all I have given one or two, to the rural areas, supplies have not been given to them.

No one side you have restricted the supply. Even the consumers are suff-

ering. In my district, a Scheduled Caste distributor had to close down, and he has resigned from dealership because you have not allotted even the cylinders. So, from one side this is happening and on the other side you are increasing the quota.

I have asked a company, "Every year Parliament Members are signing 15,000 to 16,000 letters for cylinders. What is happening?" The company says, "Now there is an embargo; we can't increase." "Then, on MPs' letters you are giving. Have you removed that embargo in the case of MPs?" The company does not know; The company says, "We do not know; we have no instructions." I am talking of Bharat Gas. Just one week before I discussed it with the company, and they said, "There is an embargo; we can't increase." But now you have increased it, at a stretch, to 38,000 cylinders; 48 multiplied by the number of MPs comes to 38,000. So, I request the honourable Minister firstly to regulate the supply. That is No. 1. No. 2: Our quota should be given to the areas from which we come. I totally disagree with my friends, Mr. Verma and Thakur Sahab.

SHRI KAPIL VERMA: I said that a Rajya Sabha Member has no constituency. The whole State is his constituency. When you say "constituency", it applies to Lok Sabha.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Actually, let this gas not become only the property of the urbanites. This gap will be widened if we only concentrate on the urban people. Let the rural people also have it. Because of our environmental conditions the village people are not getting fuel. So, will you consider taking the gas to the rural masses also? Let the rural people also feel that they are also part and parcel of this country and that they have got every right to such benefits.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): Madam, the hon. Minister's statement is self-contradictory. On the one hand there is a crisis and there

[Dr. Yelamanchili Sivaji]

is a backlog. On the other hand the Minister says that the quota of the Members of Parliament has been enhanced as if it is a great thing.

I don't think that this item warrants a *suo-motu* statement from the Minister and the Government about the enhancement of the quota of LPG connections. It is a small privilege actually.

Nothing has been mentioned about solution of the present crisis. As mentioned by my hon. friend earlier, almost all the papers are signed by the Parliament Members in the Parliament House itself or in the State Guest House itself. So, there should be an embargo. This should be allotted only for the concerned constituency. Rajya Sabha Members are also having their constituency. The entire State is their constituency, not Delhi.

In the Krishna-Godavari zone of Andhra Pradesh abundant gas potential is there. What steps have been taken by the Government to explore and exploit the gas potential there? Is there any problem of containers in supply of gas?

What steps have been taken to encourage non-conventional energy like, *go-bar gas* and other things to solve the present problem?

It is reported that a lot of gas agencies have been allotted out-of-turn quota, out-of turn priority by the Minister and the Government without channelising through the Selection Board. So, once the crisis is there, what is the rationale behind allotting out-of-turn priority to the gas agencies? I would like to know how many such agencies have been allotted by the Minister for the last five years.

Thank you.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Making use of the presence of the hon. Prime Minister, I want to ask whether the Communication Minister also who is sitting here, will also give some quota of telephone connections in a year to MPs.

कुमारी सरोज खापर्डे: मैडम, मैं बहुत बैठकर कहना चाहती थी लेकिन यहाँ आकर कहना चाहती हूँ कि अगर सबको हम बॉसल्ट करें तो सबको राब बंद है कि पैट्रोलियम मिनिस्टर का आप अनुकरण करें कि कम से कम 10 कनेक्शन एवरी इयर आप हमको दें। प्रधान मंत्री जी की उपस्थिति में आप साबुत कर ही दीजिएगा सारे देश में आसानी जब जब कार हो जाएगी। . . . (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Can we have have orde, please?

कुमारी सरोज खापर्डे: मैडम, हमारे माननीय सदस्य यह भी कह रहे हैं आपने 24 के 48 तो कर दिए लेकिन . . . (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार): मैडम, अभी पैट्रोलियम तो खत्म होने दीजिए, कन्सुमिकेशन को भी बाद में ले लीजिए। . . . (व्यवधान)

SHRI PARVATHANENI UPENDRA (Andhra Pradesh): Why do you leave Maruti cars?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा . . . (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): May we have order, in the House? (Interruptions)

श्री अरवि द गणेश कुलकर्णी: . . . मारुति एजेंसीज, वह पैसा बनायेंगी।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उप-सभाध्यक्ष महोदय, . . . (व्यवधान) अपना साहब आप बोल चुके हैं, अब तो बैठिए। इस मुल्क में 85 करोड़ जनसंख्या है और इस 85 करोड़ जनसंख्या के बारे में नहीं सोचकर सिर्फ 800 एम.पी.ज. के बारे में सोच कर मंत्री महोदय ने . . . (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): The Minister would like to say something.

SHRI S. S. AHLUWALIA: He cannot speak like this. There is a convention

in the House that before making a statement he has to give in writing to the office that he has to make a certain announcement. Why are you breaking, the convention of the House?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam, the hon. Minister wants to respond.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Mr. Ahluwalia, the Minister wants to say something I don't know what he wants to say. Would you yield or should I call him later?

SHRI S. S. AHLUWALIA: You call him later. Let me finish first.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): He does not want to yield. Let him finish. Then I will call the Minister.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: पहले एल.पी.जी. को खत्म होने दें, फिर आना टेलीफोन पर। टेलीफोन लेकर क्या करेंगे आप? ... (व्यवधान) ... 85 करोड़ जनता है इस मुल्क में और सिर्फ आठ सौ एम.पी.जी. गैस के 24 सिलिंडर्स की अंतर परमीशन देने का जो मंत्री महोदय ने निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ कि ये बधाई के पात्र नहीं हैं। ... (व्यवधान) ... आपका अपना व्यू हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के मार्केटिंग डिवीजन में कुछ दिन पहले एक सर्कुलर निकला गया है जोकि हरेक डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा गया है, उसमें कहा गया है कि जिनके पास एक कनेक्शन है उसको रिफिल करने के लिए जो दूसरी मांग आएगी उसमें 21 दिन का फर्क आना चाहिए, यह 21 दिन के फर्क की बात क्यों कही गयी है? To reduce the consumption of gas एक तरफ तो आप ऐसा सर्कुलर निकालते हैं गैस कंजप्शन को कम करने के लिए दूसरी तरफ आप एम.पी.जी. को बहलाने के लिए, उनको खुश करने के लिए 24 सिलिंडर का कोटा आप और दे रहे हैं। इससे मुल्क की 85 करोड़ जनता पर क्या असर पड़ेगा, यह सोचने की बात है? महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना

चाहती हूँ कि दिल्ली में वेटिंग लिस्ट क्या चल रही है? वह वेटिंग लिस्ट कब खत्म होगी, उसका बयान पहले दें, उसके बाद कुछ करें। महोदय, यह लिस्ट आफ विजनेस जो सुबह आयी, उसके बाद सबेरे से कुछ नहीं तो मैंने 25 टेलिफोस रिसीव किए हैं कि, साहब आपका कोटा इंक्रीज हो रहा है, मेरे नाम से चिट्ठी लिख दीजिए। महोदय, इससे जनता का क्या फायदा कर सकते हैं, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। प्रधान मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा इस मुल्क की 85 करोड़ जनता के माध्यम से कि इस एकस्ट्रा बनेफिट को वापिस लिया जाए और वापिस लेकर एक नमूना पेश करें कि पहले जो वेटिंग लिस्ट है, वह क्लियर करें और उसके बाद एम.पी.जी. को नए कनेक्शन की परमीशन दें।

संधार मंत्रालय में (स्वतंत्र प्रचार) राज्य मंत्री (डा० संजय सिंह): सम्मानित महोदय आपकी अज्ञा से, चूंकि माननीय सदस्यों की इच्छा है कि टेलिफोम भी कुछ इसी तरह आपकी सेंक्शन किए जाएं, राज्य सभा के जितने हमारे सम्मानित सदस्य हैं वे अपने जिले में 10 कनेक्शन साल में और 5 कनेक्शन पूरे देश में कहीं भी करा सकते हैं और लोकसभा के सम्मानित सदस्य अपने चुनाव क्षेत्र से 10 और पूरे देश से 5 करा सकते हैं।

कुमारी शरोज खापर्डे: मैं मंत्री महोदय को इस घोषणा का स्वागत करती हूँ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: महोदय, इस तरह से इस हाउस का कनेक्शन ब्रेक किया गया है। ऐसा स्टेटमेंट देने के पहले वाकायदा नोटस दिया जाना चाहिए। हाउस के कनेक्शन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। इस तरह तो यह खैरात बांटी जा रही है। इस देश की 85 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम पार्लियामेंट में आए हैं और हम लोग ही उनकी आवाज को नहीं उठा सकते। तो इस तरह से खैरात नहीं बांटी जा सकती। आप स्टेटमेंट दीजिए, लेकिन वाकायदा लिखित दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): He responded to the request of your colleague. (*Interruptions*) Kindly sit down, Ahluwalia Ji.

SHRI S. S. AHLUWALIA: He is breaking the convention of the House. That is the point.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I have taken note of your point and I am giving my ruling... (*Interruptions*)... Please wait. Let him finish... (*Interruptions*)... Now, I am not allowing any more discussion on the telephone... (*Interruptions*)... He responded to the request of the hon. Members of Parliament. He cannot be blamed for that.

श्री जनार्दन प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश):
मुझे तो लगता है कि खापड़ों की श्री इनकी
मिली भगत थी, पहले तैयार होकर आए
थे। खापड़ों जी को मालूम था।...
(ब्यवधान)...

DR. NAGEN SAIKIA (Assam): Madam, for the enhancement of number of LPG connections for the Members of Parliament, I want to thank Shri Satya Prakash Malaviya, Minister for Petroleum and Chemicals. I understand that already thousands of people are on the waiting list for LPG connections. If enhancement of LPG quota for MPs can at least ease the situation to a minimum extent, I think, it will be a welcome step. But before doing that the Minister will have to look after the difficulties of the consumers who are facing difficulties for years together. As I have experience, I wrote a few letters to the Minister regarding some LPG connections to some people but till today, no response has come from the Minister. I think those matters should also be looked into. Moreover, even in my place, Dibrugarh, the LPG dealer denied me the second cylinder. I had to write letters and then after six months he agreed to release the second cylinder. If he behaves with a Member of Parliament in this way, then, you can imagine very easily the plight of the general public. Moreover, I have seen that the "door delivery system" has already been abandoned by the LPG dealers. Whatever

we are speaking from this place, it is not touching them. It is not being able to move them even an inch. No "door delivery system" is being followed in the country. Moreover, they take more than two months to deliver the refill. So these are the small problems being faced by the customers which should also be looked into. In my State, in some important places, there is no LPG dealer. Therefore, I would like to request the Minister to look into these matters also.

I want to name one place, that is, Jakhala Bandha, Kaliabor, which is the constituency of the previous Chief Minister of Assam. Some people have applied for the dealership five years back but nothing has come out till today. Therefore, the Minister should see that the LPG dealerships are sanctioned to those areas where it is very much felt necessary. Thank you.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Madam, how long are we going to discuss about LPG issue? How long the discussion on communal situation is going to be sidetracked by the House? It is very strange.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I cannot prevent the Members.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: If one hour on LPG issue is taken up, what happens to the Parliament? Therefore, I put on record my strong disapproval. If this is the way... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Why don't you request your colleagues to withdraw their names?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: If this is the way the House of Elders is behaving without knowing the national... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Mr. Gurudas Das Gupta, why don't you request your colleagues to withdraw? I cannot prevent any Member from speaking.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It is very strange, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): May I request all the Members, in view of the very important discussion that we have to take up on the communal situation, not to take more than... (Interruptions)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The Prime Minister is yet to intervene.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Yes. I am calling the last name. I am not calling any more people. Shri Lotha?

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: What about my name?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Mathur sahib, I called your name but you were not here.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आपने स्वयं यह प्रथा डाली थी कि एक पार्टी से एक बोलेगा, वह तो आपने खत्म कर दी। सेक्रेटरिएट से इन्सट्रक्शन गई है कि क्लेरिफिकेशन मांगने के लिए एक पार्टी से एक सदस्य बुलाया जाएगा, आपने 10 बुलाए हैं।... (व्यवधान)... मैं केवल एक इम्पोर्टेंट चीज़ इनकी निगाह में लाना चाहूंगा और केवल एक मिनट लूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please yet him finish. (Interruptions). I cannot call every single Member who was not here. (Interruptions). Mr. Kulkarni, can we please have order in the House? Please sit down. I am calling Mr. Lotha. (Interruptions). I called you. You were not here. I am not calling all the Members who were out and who were not here when their names were called. We have to take up the communal situation now. I am calling Shri Lotha. (Interruptions).

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: You are harsh on me only.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I am not being harsh on you. I am sorry. It was including Mr. Shabbir Ahmad Salaria and Dr. Abrar Ahmed. All of them were not here.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: All right.

SHRI KHYOMO LOTH (Nagaland): Madam Vice-Chairman, I thank you for giving me this time.

The need of different regions is different. While I associate my self with the sentiments of our Members since I come from the North-East where a great deal of deforestation is rampant and forest trees are being cut down for fuel. We feel that the need for this LPG is very great. Allotments should be there not only in the normal ways but also to encourage them for protecting the forests. Because of that I thank the Minister for increasing the quota. But I would rather be happier if the number is more than this. At the same time, I would say... (Interruptions)...

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): 365 कर दीजिए ताकि प्रतिदिन एक कनेक्शन हम लोग दे सकें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please seek your clarification.

SHRI KHYOMO LOTH: I would request that the waiting list should be cleared. Not only that. For encouraging the use of LPG, more dealership agencies also should be sanctioned in the North-East. So I want to know from the Minister whether dealerships will also be increased for the people of the North-East so that the cutting down of trees for fuel may be checked to a great extent.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): If Members will be very brief, I will call those who were not called, Mr. Mathur.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं सिर्फ मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब मंत्रालय से स्वीकृति आ जाती है तो हम लोगों को यह पता नहीं लगता कि कौन से डीलर को गैस देने के लिए कहा गया है। हो क्या रहा है? हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो लेकिन 90 फीसदी मैं समझता हूँ गलत नहीं है। सेक्रेटरिएट से स्वीकृति

[श्री जगदीश प्रसाद मथुरा]

जाती है लेकिन जिस ऑयल कम्पनी को जगती है वहां पर खुले ग्राम तीन सौ, चार सौ, पांच सौ रुपये में कनेक्शन बिकते हैं। ऐसे मेरे पास उदाहरण हैं मथुरा, बुन्दावन के, जिसमें मैंने लिखा परन्तु उन्होंने कह दिया कि आर्डर चला गया और कम्पनी का अदमी कहता है कि मैं इसकी केयर नहीं करता, मैं नहीं देता। मेरे पास लिखित में उसके उत्तर हैं। तो मंत्री महोदय यह देखलें कि इनके सैक्रेटरिएट में तो नहीं लेकिन ऑयल कम्पनी दफ्तर में खुलेग्राम वहां पर रुपये से कनेक्शन बिक रहे हैं। एम पीजे के ही बिकते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि किस डीलर को आर्डर गया है। इसकी इन्वैस्टिगेशन कर ली जाये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Mr. Salaria. Please be very brief.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir): I will be very brief. Firstly, the double-cylinder system was there which obviated the need for gas connections being asked for. But that system is no longer in force. Or even if in force, it is not being complied with. I request the hon. Minister to see that that system is restored.

Secondly, there are areas, large areas, full districts in Jammu and Kashmir, in which there is no dealership and therefore, people have to go from one district to another to collect a cylinder. This difficulty may kindly be removed by giving dealership to some people there. And I can point out the areas which must be true of the rest of the country also.

Thirdly, I would like to submit that 'chulhas' are forced on the customers. When you go to get the cylinder or the connection, they ask you to purchase 'chulhas' from them when alone we will get it. This system should be stopped.

Fourthly, I would say that we have found from press reports and from some other information that huge quantities of gas are being burnt out for the reason

that we cannot harness them. Will the hon. Minister and the Government find a way out so that that energy is saved?

डा० श्री रार अहमद (राजस्थान) :—

महोदय, मैं पहली बात तो माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो कनेक्शन रिकमंड करते हैं वह कुछ ऐसे स्थानों के होते हैं जहां गैस एजेंसियां आउटरेड्डी नहीं होतीं तो उनको वहां पर गैस मिलने में या सैक्शन लेटर पहुंचने में बड़ी दिक्कत होती है। कई बार रिमाइंडर देने के बाद भी वह नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार की रिकमंडेशन के बारे में, जहां गैस एजेंसी नहीं है और एम पीजे वहां के लिए रिकमंड किया है, माननीय मंत्री जी क्या व्यवस्था करेंगे? कुछ ऐसे स्थान हैं जहां करोड़ों रुपये फॉरेस्ट को बचाने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए खर्च हो रहा है, जैसे सवाई माधोपुर में टाइगर प्रोजेक्ट है। वहां लकड़ी काटने पर पूरी पाबंदी है और इसलिए वहां जो भी काम चलाना हो वह गैस पर ही चलाया जा सकता है। तो उन स्थानों के बारे में क्या आप विशेष रूप से कुछ सोच करके बड़े सुविधाजनक तरीके से गैस उपलब्ध करायेंगे? मैं तो यह कहूंगा कि सब्सिडी के आधार पर गैस उपलब्ध करायें ताकि वे लोग वन को न काटें और गैस से अपना कार्य चलायें। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I am not calling any more names. Please sit down. There is no time. Kindly sit down.

(Interruptions).

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) :

मैंडम, इस बारे में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि ये कनेक्शन लोगों को मिलते नहीं हैं। मंत्री जी की चिट्ठी भी आ जाती है लेकिन वह ग्रामीण उपभोक्ताओं के पास नहीं पहुंचते और 6-6 महीने बाद जब वे लोग हमसे शिकायत करते हैं तो पता लगता है कि मंत्री जी ने गैस कनेक्शन किसी और को दे दिया है... (व्यवधान) यह तो हम लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात हुई... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): All right. You write a letter to the Minister.

Now please sit down. You write a letter to the Minister about your problem. Please don't disturb the Minister.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यगण श्री बागड़ोदिया, श्री खलीलुर्रहमान, श्री कपिल वर्मा, श्री नारायणस्वामी, श्री ए. जी. कुलकर्णी, श्री सुकोमल सेन, श्री हनुमंतप्पा, श्री शिवाजी, श्री अहलुवालिया, श्री जे. वी. माथुर... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी नाम गिनाना छोड़कर हमारी शंकाओं का समाधान करें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय सदस्यों ने स्पष्टीकरण मांगते हुए कुछ प्रश्न किए हैं और चोरबाजारी के संबंध में कुछ शिकायतें भी की हैं। श्री नारायणस्वामी ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि लोग माननीय सदस्यों से लिखे हुए कागजों पर हस्ताक्षर करा लेते हैं और इससे जो उनके क्षेत्र के उपभोक्ता हैं, उनको इस विशेष सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। जहां तक श्री संतोष बागड़ोदिया का प्रश्न था एलोकेशन के सिलसिले में, तो अगर किसी माननीय सदस्य ने किसी को लिखकर दिया है और उसको मिलने में दिक्कत होती है, नहीं मिलता है तो मेरे सामने जितनी भी शिकायतें आई हैं। उनको मैंने दूर करने का प्रयास किया है। फिर भी यदि किसी को शिकायत है तो वह मुझे लिखकर दे, मैं निश्चित रूप में उसे दूर करूंगा।

जहां तक चोरबाजारी का प्रश्न है, उसके लिए जो भी शिकायत मेरे पास आएगी उस पर मैं कार्यवाही करूंगा। श्री अहलुवालिया ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया था कि दिल्ली में जो बेटिंग लिस्ट है वह एक अप्रैल को चार लाख से अधिक थी। जहां तक इस सुविधा का प्रश्न है, यह पहले से चली आ रही है।

अगर माननीय सदस्यों को यह सुविधा नहीं मिलती तो उसको बढ़ाने का सवाल नहीं था।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : अगर आप जनता को वांट देते तो अच्छा रहता।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : यह जनता को मिलेगा।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : यह जनता को नहीं मिलेगा, भाई-भतीजे को मिलेगा... (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं सिर्फ यह निवेदन कर रहा था कि यह सुविधा तो माननीय सदस्यों की संस्तुतियों पर ही मिलने वाली है। जो माननीय सदस्य इसका लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, वह यदि चाहें तो अपने अधिकार का प्रयोग न करें लेकिन मेरा यह निवेदन है कि जो भी शिकायत मेरे समक्ष आएगी, उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा।

श्री शिवाजी ने एक प्रश्न जहर किया कि जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कोटा होता है मिनिस्टर का, वह कितना एलाट किया गया है? तो जब से मैं आया हूँ मैंने एक भी नहीं किया है। बाकी के बारे में मैं जानकारी प्राप्त करके बताऊंगा।

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Communal situation in the country—
Contd.

SHRI A. G. KULKARNI: Madam, before the lunch time, when I was mentioning a point, my friend, objected to certain observations. Perhaps, I may not have been correctly understood. I have all along said here that I have great respect for Mr. Advani and Mr. Vajpayee.

But I do not appreciate the logic and rational of his Rath Yatra since the Rath Yatra, I feel, is more a political gimmick